



6 FEB 1979

# भारत का राजपत्र

The Gazette of India

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

## PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० ३।

नई विस्तीर्ण, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900

No. 3]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न की जाती हैं जिसके लिए यह अलग संक्षण के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिरूप, नागरिक आपत्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय

(पारिषद्य विभाग)

सार्वजनिक सचिना सं. ३-ईटीसी(पीएन) / ७९

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

**अधिकारी :—** 1-1-1979 से 31-12-1979 तक खुले समान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशों से बने वस्त्रों का संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरोरीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों को निर्यात करने के लिए योजना।

सं० 2/26/78-ईषाई०—उपर्युक्त विषय पर नियांत (नियंत्रण) संबोधन आदेश सं० ई(सी)प्रो० 1977/ए एम (85) विनांक 1-1-79 की ओर व्याप्र ग्राहक टिक्का दिया जाता है।

2. यह योजना कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 के लिए (क) 106 व्येणियों के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संयुक्त गण्य अमरीका को; और (ख) 114 व्येणियों के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के गणराज्य प्राथमिक समवाय सदस्य राज्यों भारतीय परिषदमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेनिस्लक्स, यू.के.ओ., आथरिश गणतन्त्र और डेस्मार्क को नियर्यातों से सम्बन्धित है।

3. कोटा आबादी के उद्देश्य के लिए प्रोतलदान प्रवक्ति छ.:छ: महीनों की दो प्रवक्तियों प्रर्यात् 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1979 और 1 जुलाई, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 में विभाजित की जाएगी। वार्षिक कोट का 60 प्रतिशत प्रथम 6 महीनों के दौरान आवादित किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत अगले 6 महीनों के दौरान। सभी वस्तु

नियाति संवर्धन परियद, अमाई ऊनी वस्त्रों और बनी हुई वस्त्रों को छोड़कर वस्त्रों और बनी हुई वस्त्रों के लिए कोटों का प्राप्तंत करेगी। परिधान नियाति संवर्धन परियद, नई दिल्ली मनाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों को छोड़कर पोशाकों और मलाई से बुने वस्त्रों के लिए कोटा निर्धारित करेगी और ऊनी वस्त्रों, बनी वस्त्रों और मलाई से बने ऊनी वस्त्रों पर नरु ऊनी पोशाकों को छोड़कर, के लिए कोटे का निर्धारण ऊन व ऊनी नियाति संवर्धन परियद, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। कोटा वर्ष की प्रथम छमाही में मारा कर निर्भर करने हुए सरकार द्वारा इस विभाजन के पृष्ठ सम्बंधन पर विचार किया जा सकता है।

4. वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं के लिए कोटे का 50 प्रतिशत का निर्धारण तैयार माल के लिए पहले भाए सो पहले पाए के भाष्यार पर किया जाएगा और पें 50 प्रतिशत का निर्धारण पकड़ी संविदाओं के लिए पहले भाए सो पहले पाए के भाष्यार पर किया जाएगा। आवश्यकता पर निर्भर करते हुए तैयार माल निर्धारण और पकड़ी संविदा निर्धारण के संबंधित अनुपात का समजन जब कभी सरकार आवश्यक समझे कर सकती है।

5. पीशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए कोदे के 40 प्रतिशत का निर्धारण तैयार माल के लिए पहले प्राए सो पहले पाए के आधार पर और शेष 60 प्रतिशत पक्की संविधाओं के लिए पहले प्राए सो पहले पाए के आधार पर किया जायगा। इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक के अन्तर्मत कोटे के 20 प्रतिशत का निर्धारण उच्चतर मूल्य की मदों के लिए किया जायगा। यदि उच्चतर कीमत वाला माल स्वभाविक रूप से अन्य माल के साथ अन्य भाग में पावता प्राप्त करेगा। इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मूल्य के दो आधार होंगे—एक का संबंध 20 प्रतिशत आवंटन द्वारा उच्च मूल्य मदों के साथ और दूसरा शेष 80 प्रतिशत

आवंटन के द्वारा आने वाली मर्दों के लिए न्यूनतम सूच्य का आधार होगा। सूती पौशक और बुने हुए अस्त्रों के लिए कोटा आवंटन साथ-पत्र शर्तों पर किया जाएगा। तैयार माल के आवंटन के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर साथ-पत्र कोटा पृष्ठांकन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और पक्के प्रावेश आवंटन के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर साथ-पत्र कोटा आवंटन के 60 दिनों के भीतर अधिक प्रथमांश के लिए आवंटन कोटा पृष्ठांकन से पहले जो भी इनमें पहले आता हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कोटा आवंटन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

6. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के कोटा आवंटन के मध्ये पोतलदान कोटा पृष्ठांकन की दिनांक से 10 दिनों के भीतर प्रभावी होगा। लेकिन कई सामानों में उचित कारणों के लिए अस्त्र आयुक्त प्रथमांश के प्रतिनिधि से विशिष्ट प्रतिमोदन पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

7. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्के प्रादेश के आवंटन के भास्त्रों में, यदि प्रस्ताव अतिम तिथि तक उपलब्ध कोटा से अधिक है तो इस उद्देश्य के लिए इन प्रस्तावों में से एक प्रस्तुत की जानी चाहिए तो एकक मूल्य के आधार पर चुनाव किया जाएगा। ऐसे प्रब्लेम पर उच्च एकक मूल्य का संरक्षण होगा। उन सामानों में, अंतिम तिथि को बढ़ावा दी पोशाकों के लिए विशेष आवंटन पर विचार किया जाएगा और सुविधा प्रदान की जाएगी।

8. जहाँ कहीं सूरी, ऊनी और हाथ से बने तृण अस्त्रों के मध्ये के लिए कोटा सम्मिलित किया जाता है तो ऐसे सम्मिलित कोटा का 0.5 प्रतिशत भाग प्रत्येक ऊनी पोशाकों और हाथ से बुने हुए पोशाकों के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर भी, यह इस पर पुनः विचार किया जा सकता है और आवश्यकता पहले पर सरकार द्वारा इन मर्दों के लिए आग्रहण में आगे बढ़ि अधिक कठोरी की जा सकती है।

9. उन सामानों में जहाँ आवंटन के लिए हथकरघा और मिल द्वारा बनाए हुए मर्दों का इकट्ठा किया जाता है, अमरीका के सामानों में तृणों के लिए हथकरघा का अनुपात 2:1 होगा; जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए यह 1:1 होगा। सांग की स्थिति को बेबते हुए इन अनुपातों में संरक्षण भी किए जा सकते हैं।

10. इस उद्देश्य के लिए मनोनीत नियर्ति संबंधित परिषद् द्वारा जारी किए गए अलग-अलग परंपराओं के लिए पोतलदान परिवहन विलों की मूल और द्वितीय प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर पोतलदानों की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पतनों पर दी जाएगी। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में पोतलदानों की अनुमति देने से पहले अस्त्रद्वारा नियर्ति संबंधित परिषद् या इसके प्राधिकारित प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए विशेष सीमाशुल्क बीजक में 0.5/5 पर सीमाशुल्क प्राधिकारी बींगा पृष्ठांकन का भी गतिपान करेंगे। यूरोपीय आधिक समुदाय सदस्य राज्यों की नियर्तियों के सम्बन्ध में कोटा पृष्ठांकन के साथ सम्बद्ध नियर्ति संबंधित परिषद् नियर्ति प्रभाणपत्र और अलग-अलग सीमा श्रेणी रखने वाले श्रेणियों के लिए उद्घम प्रभाणपत्र और अलग-अलग सीमा श्रेणी न रखने वाली अन्य श्रेणियों के उद्घम प्रभाणपत्र जारी करेंगी; ये प्रभाणपत्र गतिव्य स्थानों पर निकामी प्राप्त करने के लिए आयातकों को खेजने के लिए होंगे।

11. इस योजना के अन्तर्गत शामिल वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां अस्त्रद्वारा नियर्ति संबंधित परिषद् के पास उपलब्ध हैं।

12. जहाँ तक संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आधिक समुदाय को हथकर्धा वस्त्रों, हथकर्धा वस्त्रों से बनी वस्तुओं और यूरोपीय आधिक समुदाय के संबंध में श्रेणी 7, 8, 26 और 27 श्रेणियों से विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले हथकर्धा वस्त्रों से तैयार कई हुई पोशाकों

के संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आधिक समुदाय को नियर्ति का अस्त्रद्वारा है। पोतलदानों की अनुमति सम्बद्ध नियर्ति संबंधित परिषद् द्वारा कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकताओं के बिना सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा वस्त्र समिति के प्रभाणन के आधार पर दी जाएगी। संयुक्त राज्य अमरीका को श्रेणी 336, 340, 341, 347 और 348 के अन्तर्गत आने वाले हथकर्धा की पोशाकों के नियर्ति के लिए वस्त्र समिति द्वारा प्रभाणन परिधान नियर्ति संबंधित परिषद् द्वारा कोटा आवंटन के आधार पर आर्द्ध किया जाएगा।

13. जो भारतीय मर्दे विशेष रूप से भारतीय परम्परागत लोकवस्त्र उत्पाद हैं उनके सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आधिक समुदाय को नियर्तियों के लिए अस्त्रिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वर्तमान समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रभाणपत्रों के आधार पर सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अनुमति दी जाएगी। भारत मर्दों के रूप में प्रभाणन मर्दों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पांत परिवहन विलों के पृष्ठांकन के लिए सम्बद्ध नियर्ति संबंधित परिषदों द्वारा किसी भी कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

14. वस्त्र आयुक्त अस्त्रद्वारा या उसके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी कोटा नियर्तिरण से सम्बंधित सामानों पर विन प्रतिदिन पर्यवेक्षण चलेगा। विभिन्न सम्बद्ध नियर्ति संबंधित परिषदों के प्रतिनिधियों नहिं वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति समय-समय पर परिस्थिति का पुनरीक्षा करेंगी।

15. पोशाकों और जलाई में बने वस्त्रों के लिए कोटा आवंटन के जहाँ पर्यन्त लोकवस्त्र के 10 प्रतिशत मूल्य के लिए आवेदक द्वारा निष्पादन बाष्ठ पहले आए सो पहले पाए, पक्की मविदा के आधार पर आवंटन के लिए आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटा नियर्तिरण के सामानों में प्रति नग एक स्पष्ट या जहाँपर्यन्त लोकवस्त्र मूल्य का 10 प्रतिशत और भी अधिक हो, की दर पर अधिक धन आवेदक को कोटा पृष्ठांकन के समय जमा करना होगा। यदि कोटा आवंटन/कोटा पृष्ठांकन का बैंडना अर्वाध के भीतर 90 प्रतिशत से कम उपयोग होता तो नियर्ति का नाम प्रत्यनुत करने पर जमा किए गए अधिक धन/कोटा नियर्तिरण का पूरा अन्यान्य वापिस कर दी जाएगी। यदि कोटा नियर्तिरण का उपयोग 90 प्रतिशत से कम होता तो निष्पादन बाष्ठ की पूर्ण व्यवहारण के लिए जुर्माना किया जाएगा, और जमा किया गया पूर्ण अधिक धन जमा किया जा सकता है। यदि कोटे का अध्यक्षण आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक तारा ने ऐसे आवंटन के लिए आए कोटा आवंटन को मना करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन प्रधान शक्ति की शर्तों में उपग्रहण बूट पर विचार किया जा सकता है।

16. नियर्ति की अनुमति भारत के भारत में किसी भी नन्हे में दी जाएगी।

17. नियर्ति संबंधित परिषदों के पते निम्नलिखित अनुमार

(1) सूती वस्त्र नियर्ति संबंधित परिषद्

"इंजीनियरिंग सेस्टर,

9, मेट्यू रोड, पांचवीं मंजिल,

बम्बई-400004।

(2) परिधान नियर्ति संबंधित परिषद्,

सहूली विलिंग, चौथी मंजिल,

50 नेहरू प्लैस, नई विल्सो-110019।

(3) ऊनी और ऊनी वस्त्र नियर्ति संबंधित परिषद्,

714 अमोक एस्टेट,

24 बागबाबा रोड, नई विल्सो-110001।

18. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार जिन व्यक्तियों का कोटा प्राप्त किया गया है लेकिन जो उसको पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं आते हैं उनके विशेष जो इस सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई की जा सकती है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दाते बिना ही उन्हें भविष्य में कोटा प्राप्त करने के लिए चांगित किया जा सकता है।

19. 1978-79 की नियर्यात नीति में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाएँगे :

क्रम पृष्ठ सं.	मन्त्री	संशोधन
मं.		
1. 28 पृष्ठ 29	क्रमसं: क्रम सं० नं० 70 (v) और नं० 70 (vi) के मामते कानूनम् 3 में	विद्यमान अभियुक्ति सं० 1 निम्न- लिखित अनुसार पढ़ने के लिए मणिधित की जाएगी :— “निम्नलिखित द्वारा कोटा आव- टन के मद्दे— (क) सूती वस्त्र नियर्यात मंवधन परिषद्, ऊनी वस्त्र और उनसे बनी हुई वस्तुओं को छोड़कर वस्त्रों और उन से बनी हुई वस्तुओं के लिए सूती वस्त्र नियर्यात मंवधन परिषद् मलाई से बनी हुए ऊनी वस्त्रों को छोड़कर पोशाकों और मलाई से बने हुए वस्त्रों के लिए। (ग) ऊन और ऊनी नियर्यात मंवधन परिषद्, ऊनी वस्त्रों में बनी वस्तुओं और मलाई में बने हुए ऊनी वस्त्रों के निए परन्तु ऊनी पोशाकों को छोड़कर। पानखदान बिनों पर पृष्ठाकृत ब्रान।” का० श्र० शेषाद्रि, मुख्य नियन्त्रक आयात-नियर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

### (Department of Commerce)

#### PUBLIC NOTICE NO. 2-ETC (PN)/79

New Delhi, the 1st January, 1979

### EXPORT TRADE CONTROL

1. Scheme for exports under OGL 3 of textiles made from cotton, wool and man-made fibres to USA and EEC Member States from 1-1-1979 to 31-12-1979.

2. 2/26/78-EI.—Attention is invited to the Exports (Cont.-Amendment Order No. E(C) O. 1977/AM(85) dated 1979 on the above subject.

The scheme relates to the exports of textiles (a) falling or 106 categories to the USA and (b) 114 categories to EEC Member States, viz., West Germany, France, Italy, Lux, U.K., Irish Republic and Denmark for the quota year January, 1979 to 31st December, 1979.

3. For the purposes of quota allotment, Shipment period will be divided into two six-monthly periods, i.e. from 1st January, 1979 to 30th June, 1979 and from 1st July, 1979 to 31st December, 1979. 60% of the annual quota will be allocated during the first six months and the rest 40% during the next six months. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay will allocate quotas for fabrics and made-ups excluding woollen fabrics and made-ups. The Apparels Export Promotion Council, New Delhi will allocate quota for garments and knitwear excluding woollen knitwear and the allocation for woollen fabrics, made-ups and woollen knitwear but excluding woollen garments will be made by the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi. Depending upon the demand in the first-half of the quota year, readjustments of this division may be considered by the Government.

4. For fabrics and made-up articles, 50% of the quota will be allocated on first-come first-served basis for ready goods and the rest 50% on first-come first served basis for firm contracts. Depending upon the need, adjustment of the related proportion of ready goods allocation and firm contracts allocation may be made by the Government whenever it is found necessary.

5. For garments and knitwear, 40% of the quota will be allocated on first-come first-served basis for ready goods and the rest 60% on first come first served basis for firm contracts. Under each of these two systems, 20% of the quota will be allocated for higher value items. In case the portion for higher price allocation gets exhausted first, the goods with higher price will naturally have the eligibility in the other portion alongwith the other goods. For this purpose there will be two sets of floor prices - one relating to higher value items covered by 20% allocation and the other basic floor price for items covered by the remaining 80% of the allocation. Quota allocation for cotton garments and knitwear will be made on LC terms. For first-come first-served ready goods allocation, LC should be produced at the time of quota endorsement and for first-come first-served firm contract allocation, LC should be produced within 60 days of quota allocation or before quota endorsement for shipment, whichever is earlier, failing which quota allocation will be automatically deemed to lapse.

6. Shipments against quota allocations on first-come first-served ready goods basis will have to be effected within 10 days from the date of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional cases for valid reasons in specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

7. In the case of first-come first-served firm contract allocation, if the offers are more than the quota available on the terminal date, a choice among offers may have to be made and, for this purpose, selection will be made on the basis of unit price. The higher unit price will be the criterion in such an eventuality. In that case, on the terminal date special allocation for children's garments will be considered and provided.

8. Wherever the quotas for cotton, woollen and man-made fibres items are combined, 0.5% of such combined quotas have been reserved each for woollen garments and man-made fibres garments. This is, however, subject to review and, if necessary, a further enhancement or reduction in the reservation for these items may be made by Government.

9. In cases where handloom and millmade items are clubbed together for allocation, the ratio of handloom to others in the case of the USA will be 2 : 1, whereas it will be 1 : 1 for other areas. These ratios may be amended depending upon the trend of demand.

10. Shipments will be allowed by the Customs Authorities at the ports of shipment on the basis of quota en l'aisement on the original and duplicate of the shipping bills for individual consignments issued by the Export Promotion Council designated for this purpose. In respect of USA, however, before allowing shipments, the Customs Authorities would also verify the visa endorsement on the Special Customs Invoice No. 5515 issued by the Export Promotion Council concerned or its authorised representatives. In respect of exports to EEC Member States, alongwith the quota endorsement, the Export Promotion Council concerned will issue export certificate and certificate of origin for categories having individual category limits and certificate of origin in respect of other categories not having individual category limits for forwarding these certificates to importers for obtaining clearance at the destination.

11. The lists of categories of textile products covered under the scheme are available with the Export Promotion Councils concerned.

12. In so far as exports to USA and EEC of handloom fabrics, made-up articles made from handloom fabrics and woven garments made from handloom fabrics falling under categories other than categories 7, 8, 26 and 27 in respect of EEC are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textiles Committee without the requirements of the quota endorsement by the Export Promotion Councils concerned. In the case of handloom garments falling under categories 336, 340, 341 347 and 348 for exports to USA, certification by the Textiles Committee will be issued on the basis of quota allotment by the Apparels Export Promotion Council.

13. In respect of India items which are typically Indian traditional folklore textile products, shipments will be permitted by the Customs for exports to USA and EEC on the basis of appropriate certificates issued by All India Handicrafts Board or the Textiles Committee. For items certified as India items, no quota endorsement by the Export Promotion Councils concerned will be required for endorsement of the shipping bills by the Customs Authorities.

14. The Textile Commissioner, Bombay, or an officer designated by him will have a day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as the Chairman and representatives of various Export Promotion Councils concerned will review the situation from time to time.

15. For garments and knitwear, performance bond for a value of 10% of the f.o.b. value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on first-come first-served firm contract ready. In the case of quota allocation on first-come first served ready goods basis, earnest money at the rate of Re. 1/- per piece or 10% of the f.o.b. value, whichever is higher, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90%, full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on production of evidence of export. If the utilisation of quota allocation is less than 90%, penalty for the full amount of the performance bond will be imposed, and the full earnest money deposited will be liable to be forfeited. Further, if the surrender of quota is in excess of 25% of allotments, refusal of further quota allotment for such allottees may be considered. However in conditions of force majeure, appropriate exemptions may be considered.

16. Exports will be allowed from any port in India.

17. The addresses of the Export Promotion Councils are as follows :—

- (i) The Cotton Textiles Export Promotion Council, 'Engineering Centre', 9, Mathew Road, 5th Floor, Bombay-400004.
- (ii) Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building, 4th Floor, 59, Nehru Place, New Delhi-110019.

(iii) Wool and Woollens Export Promotion Council, 714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

18. Persons to whom quotas are allotted in accordance w. the above arrangements but who do not utilise them fe. would be liable to disqualifications from getting future quotas without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

19. The following amendments shall hereby be made in the Export Policy, 1978-79 :—

S. No.	Page No.	Reference	amendment
1.	¶28 and 29	In Column 3 against S. No. 70(v) and 70 (vi) respectively.	The existing remark No. 1 shall be amended to read as under: "Against quota allotment by Promotion Council for fabrics and made-up excluding woollen fabrics and made-up:
			(b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwears excluding woollen Knitwear
			(c) Wool and Woollen Export Promotion Council for woollen fabrics made-ups and woollen knitwear but excluding woollen garments by endorser on shipping b'

[Issued from file No. 2/26/1]

K. V. SESHAI  
Chief Controller of Imports & Exports